

SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (JHARKHAND), 2009-10

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI NAMO NARAIN MEENA):
Sir, I beg to lay on the Table, a statement (in English and Hindi) of the estimated receipts and expenditure of the State of Jharkhand for the year 2009-10.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, we shall take up the Short Duration Discussion on Price Rise. Mr. Kalraj Mishra.

SHORT DURATION DISCUSSION

Situation arising out of continued rise in prices of essential commodities in the country

श्री कलराज मिश्र (उत्तर प्रदेश) : उपसभापति महोदय, मूल्य वृद्धि जिस स्तर से हो रही है उसको देखने के बाद यह लगता है कि सामान्य गरीब व्यक्ति ही नहीं, मध्यम वर्गीय से लेकर सभी लोग इससे जबर्दस्त प्रभावित हो रहे हैं। हालात ऐसे होते जा रहे हैं कि सरकार जितनी बार घोषणा करती है कि हम नियंत्रण करेंगे, जल्दी ही करेंगे, धैर्य रखना चाहिए, उतनी तेजी के साथ महंगाई बढ़ती जा रही है। अगर हम अपने इस विशाल देश की स्थिति को देखें तो हमें दिखाई पड़ेगा कि अधिकांश लोग गरीबी की रेखा के नीचे की जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। ऐसे हालात हैं कि सामान्य समय में भी आजीविका की, भरण-पोषण की जो उनकी व्यवस्था होनी चाहिए, वह भी कर सकने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। ऐसी स्थिति है। इसलिए देश का हर चौथा व्यक्ति एक ओर भूखा रहता है। चार वर्षों में देश में भूख से मरने वालों की तादाद चार हजार आठ सौ हो गई है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन UNFAO की जो रिपोर्ट है, उन्होंने कहा है कि दुनिया के सबसे ज्यादा गरीब तथा भूख और कुपोषण से पीड़ित तेइस करोड़ तीस लाख लोग भारत में हैं। देश में गरीब आदमी की आमदनी खाद्य मूल्य वृद्धि के अनुपात में नहीं बढ़ी। एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा था कि भारत के लोग ज्यादा खाते हैं। लेकिन जो आंकड़े हैं, आंकड़े तो यह बताते हैं कि जब आम आदमी को खाद्य पदार्थ ही उपलब्ध नहीं हो पा रहा है तो वह खाना कहां से खाएगा। 1999 में खाद्य खपत प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 186 किलोग्राम था, आज खाद्य खपत प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 152 किलोग्राम है, यानी खाद्यान्न खपत प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 45 किलोग्राम कम हो गई है। सरकार के आंकड़ों के अनुसार ही आबादी का 28.5 फीसदी इतने लोग गरीबी रेखा के नीचे की जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं, अर्थात् सात करोड़ परिवार, अर्थात् 35 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे की जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। भारत सरकार ने अर्जुन सेन गुप्ता कमेटी गठित की थी। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर देश के 77 फीसदी नागरिकों की आय प्रतिदिन बीस रुपया है। इस प्रकार 77 परसेंट नागरिकों की आय बीस रुपया है। बीस रुपए में आम आदमी आटा, दाल, तेल, चावल क्या खरीद पाएगा, उसकी क्या हालत होगी। मान्यवर, देश में जो गरीबी की स्थिति है, उसमें बहुत ज्यादा सुधार तो नहीं दिखाई पड़ता, यद्यपि हम जरूर यह कहते हैं कि हमारी विकास दर बढ़ती जा रही है, परचेंसिंग पावर बढ़ती जा रही है, लेकिन गरीबी भी उसी तरह से बढ़ती जा रही है। सर, मैं जो आंकड़े दे रहा हूं, ये आंकड़े 11वीं पंचवर्षीय योजना की वार्षिक योजना की रिपोर्ट तथा आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट से लिए गए हैं, ये अन्यथा आंकड़े नहीं हैं। 35 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में तीन राज्यों - बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में आबादी का 40 फीसदी लोग गरीबी की जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। गरीबों की कुल संख्या का दो तिहाई छः राज्यों में उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में है।